Knowledgeable Research **Vol-1, No-3, *October 2022***

An International Open-access Peer-reviewed Journal **Web: http://www.knowledgeableresearch.com/**

भारत में शिक्षा की उभरती समस्याएँ एवं कठिन परिस्थितियाँ

डॉ उदय प्रताप सिंह

असिस्टेंट प्रोफेसर , बी.एड. विभाग

किसान पी.जी. कॉलेज ,बहराइच (यू.पी.)

ईमेल : udaysinghedu2610@gmail.com

****

शोध सारांश

शिक्षा किसी देश के विकास में सहायक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसे समय की जरूरतों और दुनिया के बदलते परिदृश्य के अनुरूप बदलना होगा। यह मानवता से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और गैर-धर्मनिरपेक्ष समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का अवसर प्रदान करता है। भारत अपनी वित्तीय प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए अधिक हरित और शिक्षित मनुष्यों की इच्छा रखता है। दुनिया भर में ऐसे कई भारतीय हैं जो अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के लिए पहचाने जाते हैं। भारत को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विस्तारित करने या वैश्विक आर्थिक प्रणाली में एक समृद्ध भागीदार बनने के लिए, भारत को विशेष रूप से अनुसंधान और सुधार के साथ मानक और उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को गुणात्मक रूप से बढ़ाना होगा। यह पेपर विशेष रूप से भारत में उच्च प्रशिक्षण मशीन के सामान्य समग्र प्रदर्शन पर केंद्रित है। हम स्कूली शिक्षा प्रणाली के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का पता लगाने का प्रयास करते हैं। यह पेपर भारत में बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं और चुनौतियों की खोज करने की महत्वाकांक्षा रखता है। अंत में पेपर यहीं समाप्त होता है कि ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है जो समाधानों की आवश्यकता है जो नियोक्ताओं और युवाओं को विभिन्न हितधारकों कॉलेज के छात्रों, उद्योग, शैक्षणिक प्रतिष्ठानों, माता-पिता और सरकार से अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता है।

Keywords: *शिक्षा, भारत, समस्याओं, परिस्थितियाँ*

****

प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील संयुक्त राज्य के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह बढ़ते मानव विकास को प्रोत्साहित कर रही है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में उच्च शिक्षा में असाधारण विस्तार हुआ है। भारत ने वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रौद्योगिकीविद्, डॉक्टर, शिक्षक और प्रबंधक पैदा किए हैं जिनकी पूरी दुनिया में आश्चर्यजनक मांग है। अब यह हमारी औद्योगिक और तकनीकी क्षमता में शीर्ष दस देशों में से एक है, विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के माध्यम से प्रदान की गई जनशक्ति और उपकरणों के बड़े योगदान के कारण। भारत पहले ही विशेषज्ञता विस्फोट के युग में प्रवेश कर चुका है। इसने परमाणु और क्षेत्रीय क्षेत्रों में अपने समग्र प्रदर्शन का उपयोग करके अपनी बेहद अच्छी व्यावहारिकता साबित की है। आने वाले कुछ दशकों में अंतरिक्ष यान, उपग्रह, इंटरनेट और वैज्ञानिक जांच की अन्य शाखाओं के माध्यम से शुरुआत की जाएगी। उच्च शिक्षा लोगों को मानवता से संबंधित मूलभूत सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक समस्याओं पर विचार करने की संभावनाएँ प्रदान करती है। उच्च विद्यालयी शिक्षा राष्ट्रीय विकास के लिए विशेष जानकारी और जानकार व्यक्ति प्रदान करती है। अगले कुछ दशकों में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्ग होगा। जबकि मनुष्य और उच्च स्कूली शिक्षा के बीच संबंध अब

ठीक नहीं रह गया है। बढ़ती युवा आबादी हो सकती है

यदि संभावित रोजगार योग्यता को फलीभूत किया जाए तो यह बड़ी संपत्ति है। इसके विपरीत, यदि हम प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने में विफल रहते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक द्वार खोल देगा। स्थिरता प्राप्त करने के लिए शिक्षा एक अनिवार्य उपकरण है। शिक्षा आयोग 1964-66 ने एक कथन के माध्यम से सामाजिक और वित्तीय परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन किया- किसी राष्ट्र का घनत्व उसके वर्ग कक्षों में बनता है। शिक्षा सृजन करती है मानव पूंजी मौद्रिक विकास का मूल है और यह मानता है कि मानव पूंजी द्वारा उत्पन्न बाह्यताएं आत्मनिर्भर मौद्रिक प्रक्रिया का स्रोत हैं। 1951 के बाद से उच्च शिक्षा में काफी तेजी आई है। विश्वविद्यालय स्तर के प्रतिष्ठानों और स्कूलों की संख्या बढ़ी है 1951 से 2014 तक क्रमशः 28 से 677 और 578 से 3800 हो गए। परिणामस्वरूप, शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। छात्रों के नामांकन में वृद्धि समय के साथ शिक्षकों की संख्या में वृद्धि से अधिक है, इसके अलावा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के रूप में कॉलेज स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से भारी वित्त पोषण भी हो सकता है। संकाय स्तर पर नामांकन और प्रतिष्ठानों में वृद्धि, उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों में तेजी से वृद्धि हो रही है 2014 के अंत में भारत में 677 विश्वविद्यालय और 38000 संकाय थे। लेकिन फिर भी हमें मांग को पूरा करने के लिए 1500 से अधिक विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। तालिका 1 से पता चलता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अब न केवल विभिन्न प्रकार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बल्कि नामांकन में भी सुधार कर रही है। इनमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों में संबद्ध कॉलेज हैं जहां स्नातक प्रकाशनों को मंजूरी दी जाती है और पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी, अगर हम बढ़ती आबादी के साथ इस सुधार की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें पुनर्विचार करना होगा, क्या यह फिर भी 2010-2011 में डेस्क -2 में प्रकाशित उच्च शिक्षा डिग्री वार विद्वान नामांकन लड़कों और महिलाओं की वृद्धि को बढ़ा रहा है। तथ्य यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का नामांकन अनुपात कम है। जानकारी स्पष्ट रूप से इस वास्तविकता को बयां करती है कि नामांकन अंतर लुकअप में 19 प्रतिशत के साथ देखा गया है और उसके बाद स्नातक में 17 प्रतिशत के साथ आया है और उसके बाद स्नातकोत्तर में 13 प्रतिशत के साथ आया है।

ज्ञान अर्थव्यवस्था की उभरती स्थिति में व्यापक स्कूली शिक्षा की भूमिका आम तौर पर किसी भी देश और विशेष रूप से भारत के लिए बहुत अपरिहार्य और बहुआयामी है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली के रास्ते में कई बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें शिक्षा की गुणवत्ता के निचले चरण, उच्च शिक्षा का वित्तपोषण, यथार्थवादी ज्ञान की तुलना में सिद्धांतों और वैकल्पिक पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, शिक्षण की पारंपरिक रणनीतियाँ, निजीकरण, अपर्याप्त सेवाएं और बुनियादी ढांचा कोटा प्रणाली शामिल हैं।

शिक्षण गुणवत्ता का निम्न स्तर:

हमारी प्रशिक्षण मशीन अपने कई प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों में जुर्माने के मुद्दों का उपयोग करके अत्याचार कर रही है। संकाय की कमी, भयानक असाधारण शिक्षण, पारंपरिक शिक्षण पद्धति, पुरानी और कठोर पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र, जवाबदेही और अच्छे आश्वासन की कमी और अध्ययन और शिक्षण का पृथक्करण जैसे कई मुद्दे भारतीय शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हैं।

उच्च शिक्षा का वित्तपोषण:

सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक जिस पर गौर किया जाना चाहिए वह है सरकार के समक्ष अधिक प्रशिक्षण से जुड़ी आर्थिक बाधाओं की समस्या। सामान्य शिक्षा पर और वास्तव में सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर खर्च, पूरे देश के लिए

शिक्षा में उत्कृष्टता निर्धारित करने के मापदंडों में से एक है। राज्य सरकार पहले से ही अपने राजस्व बजट का 20-30 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रही है। इसे और अधिक खर्च करने के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। भारत में, उच्च शिक्षा ने विभिन्न स्तरों की तुलना में सार्वजनिक व्यय के मामले में बहुत कम रुचि प्राप्त की है। भारत के लिए अनुसंधान और विकास में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय निवेश करना व्यवहार्य नहीं है, जिसने पश्चिम में एमआईटी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, अमेरिका में बर्कले या ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे लुकअप नेतृत्व वाले विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। व्यावहारिक ज्ञान के बजाय सिद्धांतों और वैकल्पिक पर अधिक ध्यान केंद्रित: भारतीय शिक्षा प्रणाली यथार्थवादी ज्ञान के बजाय सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है। कई नौकरियों में न्यूनतम प्रतिशत की भी आवश्यकता होती है जो कि अधिक होती है।

शिक्षण के पारंपरिक तरीके:

प्रोफेसर अभी भी बोर्ड, मार्कर जैसी शिक्षण की इन पुरानी तकनीकों से चिपके हुए हैं। वे शिक्षण में दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग करना पसंद नहीं करते। इसके अलावा, वे अब उपलब्ध आंकड़ों और अंतरराष्ट्रीय उद्योग की मांगों से भी अपडेट नहीं हैं।

कोटा प्रणाली:

स्कूली शिक्षा में विशिष्ट श्रेणियों के लिए आरक्षण और कोटा प्रणाली लाने से इसकी गुणवत्ता ख़राब हो गई। यहां तक कि रोजमर्रा की कक्षाओं के योग्य उम्मीदवारों को भी छोड़ दिया जाता है और कोटा में हमें आरक्षित वर्ग से किसी अन्य व्यक्ति का चयन करना पड़ता है, भले ही वह उपयुक्त न हो।

भारतीय उच्च शिक्षा की मशीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मशीन है जो समाज के विशिष्ट वर्गों से आने वाले लाखों छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करती है क्योंकि यह छात्र समुदाय ही है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में संपूर्ण ट्यूटोरियल पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न करने में सहायता कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत आजकल गरीबी, बेरोजगारी, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के लुप्त होने से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों का सामना कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ लम्बे समय में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में देशव्यापी समस्याएँ/चुनौतियाँ सामने आई हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार है।

निजीकरण:

मौजूदा परिदृश्य में, उच्च शिक्षा का निजीकरण आश्चर्यजनक रूप से एक नवोदित लेकिन स्वागत योग्य प्रचलन है और रचनात्मकता, अनुकूलनशीलता और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उदारीकरण और वैश्वीकरण का मौद्रिक पथ इसकी मांग करता है। भारत में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत दोनों संस्थाएँ एक साथ कार्य करती हैं। भारत में लगभग 50 प्रतिशत उच्च शिक्षा निजी संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाती है, आमतौर पर बिना सहायता के जिसमें अत्यधिक लागत शामिल होती है। हालाँकि, स्थिति इतनी सरल नहीं है। निजी प्रदाता, अधिकतम लाभ कमाने के शौक में, अपने संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा के आनंद से समझौता करके 'लागत कम करने' के लिए हर प्रोत्साहन रखते हैं। अंतिम लेकिन कम से कम, शिक्षण कार्यबल की असाधारणता भविष्य में उच्च स्कूली शिक्षा तिमाही के लिए व्यापक समस्याओं में से एक है। इससे पहले, वे अपने छात्रों, उनके विषयों और उनके पेशे के प्रति प्रतिबद्ध थे। आज वेतन तो बहुत मिल जाता है लेकिन प्रतिबद्धता कम होती है। इस प्रकार, उच्च शिक्षा प्रणाली को अनावश्यक बाधाओं और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना समय की मांग है।

अपर्याप्त सेवाएँ और बुनियादी ढाँचा:

भारत में, कई विश्वविद्यालयों में छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा या सुविधाएँ नहीं हैं। यहां तक कि कई निजी विश्वविद्यालय भी बिना कक्षाओं के जॉगिंग पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इंटरनेट और वाई-फाई की सुविधा अभी भी कई छात्रों की पहुंच से बाहर है।

हमारी विषम शिक्षा प्रणाली:

भौगोलिक, ग्रामीण-शहरी, अमीर-गरीब व्यवस्था के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अद्भुत परियोजना प्रस्तुत की गई है। विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों ने विभिन्न प्रकार और गुणवत्ता वाली शिक्षा का उत्पादन किया है। उनमें से कुछ वास्तव में गुणात्मक स्कूली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य सबसे गंदा काम कर रहे हैं। शैक्षणिक कदाचार में लिप्त ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों और संस्थानों की सूची प्रकाशित करने के लिए यूजीसी को धन्यवाद।

निष्कर्ष

1.निष्कर्ष शब्दों में, हम कह सकते हैं कि समय के साथ, संस्थानों, नामांकन आदि के संदर्भ में अधिक से अधिक प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अब पर्याप्त नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च शिक्षा से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें शानदार कवरेज निर्माण और उनके अच्छे कार्यान्वयन के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है।

2. भारत में उच्च शिक्षा कई भूमिकाएँ निभाती है। यह कई लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सुधारों को नियमित रूप से विशिष्ट, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए अच्छे आकार के खतरों के रूप में देखा जाता है जो शक्तिशाली समूहों को लाभ प्रदान करते हैं।

संदर्भ

- मिश्रा शारदा, (2006)। भारत में यूजीसी और उच्च शिक्षा प्रणाली। बुक एन्क्लेयर, जयपुर.302006.
- अरुणाचलम पी. भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र: मुद्दे और अनिवार्यताएं। जर्नल ऑफ़ ग्लोबल इकोनॉम 2010; 6(4)
- पाढ़ी, एस.के. (2011), 'ज्ञान समाज के लिए उच्च शिक्षा में मुद्दे, चुनौतियाँ और सुधार,'
- भारत में उच्च शिक्षा: मुद्दे, चिंताएँ और नई दिशाएँ http://www.ugc.ac.in/pub/heindia.pdf
- रमेश जी. भारतीय उच्च शिक्षा और स्थिरता की चुनौतियाँ: एक विश्लेषणात्मक नोट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च 2013; 2(9).